**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड**

**55वीं बैठक दिनांक 19 नवम्‍बर, 2015**

**कार्यवृत्त**

राज्‍य स्‍तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 55वीं बैठक दिनांक 19 नवम्‍बर, 2015 को श्रीमती डा. इंदिरा हृदयेश, मा. वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड की अध्‍यक्षता में संपन्‍न हुई। इस बैठक में श्री शत्रुघ्न सिंह, मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, समस्‍त बैंक / बीमा कंपनी एवं शासकीय विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ महत्‍वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गयी।

**श्री बी. के. दास, महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक**

महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक ने माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड, राज्‍य प्रशासन, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, बीमा कंपनियों, बी.एस.एन.एल. एवं बैंकों के उच्‍च अधिकारियों का एस.एल.बी.सी. की 55वीं **बैठक** में पधारने पर आभार प्रकट किया और श्री शत्रुघ्‍न सिंह जी को उत्तराखंड राज्‍य के मुख्‍य सचिव का पदभार संभालने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

बैंक द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑनलाइन प्रभार अंकित करना:

**( Online Creation of Charge on Land Records by Bank )**

**राज्‍य सरकार एवं एन.आई.सी. द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने से संबंधित सॉफ्‍टवेयर को सफलतापूर्वक चुनिन्‍दा बैंक शाखाओं में Trial run कराए जाने पर महाप्रबंधक महोदय ने प्रसन्‍नता व्‍यक्‍त करते हुए राज्‍य सरकार एवं एन.आई.सी. को समस्‍त सहयोगी बैंकों की ओर से धन्‍यवाद दिया और आशा व्‍य‍क्‍त की, कि अब शीघ्र ही सभी बैंक शाखाओं को ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी ।**

**ॠण-जमा अनुपात**

उन्‍होंने सदन को बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वितीय तिमाही में राज्‍य का ॠण-जमा अनुपात लगभग 57 % है, जिसे सभी बैंकों के सहयोग से माह दिसम्‍बर, 2015 तक 60 % से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। उन्‍होंने राज्‍य सरकार से अनुरोध किया कि सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया जाए कि व़े Cluster based bankable schemes in accordance with the specific areas बनाकर, क्रियान्‍वयन हेतु संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक को भेजे जाए।

**कृषि ॠण :**

महाप्रबंधक महोदय ने बैंकों से आग्रह किया कि सभी पात्र कृषकों का फसली बीमा दिनांक 31 दिसम्‍बर, 2015 तक अनिवार्य रूप से करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने आगे कहा कि सभी बैंक विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाकर कृषि ऋण के साथ साथ स्वयं सहायता समूहों का भी बैंक लिंकेज करें।

अंत में उन्‍होंने सदन में उपस्थित सभी का धन्‍यवाद किया और विश्‍वास प्रकट किया कि सभी बैंक, राज्‍य सरकार के सहयोग से राज्‍य के विकास में प्रत्‍यनशील रहेंगे।

**श्रीमती डा. इंदिरा हृदयेश जी, माननीय वित्त मंत्री,उत्तराखंड**

माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्‍य की आर्थिकी को सुदृढ़ बनाने में बैंकों से बहुत अपेक्षाएं हैं और सुझाव दिया कि अगर हम स्‍वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक संख्‍या में वित्तपोषित करें और जो समूह निष्क्रिय हो गए हैं अगर बैंक थोड़ा बहुत जोखिम लेकर उन्‍हें पुनर्वित्तपोषित करेंगे तो एस.एच.जी. के एन.पी.ए. में कमी आने की प्रबल संभावना है। आगे उन्‍होंने कहा कि अगर हम एक एस.एच.जी. को आर्थिक रूप से सशक्‍त बनाने में सफल होते हैं तो हम कम से कम आठ-दस लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत तो करते ही हैं साथ ही उन्‍हें महाजनों एवं साहूकारों से छूटकारा दिलाने में सहायक होंगे।

उन्‍होंने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया और कहा कि बैंक कृषि ॠण संबंधी जानकारियाँ प्रदान करने एवं कृषकों को अधिक से अधिक संख्‍या में किसान क्रेडिट कार्ड

उपलब्‍ध कराने हेतु गढ़वाल एवं कुमायूँ क्षेत्र में शिविर लगाएं, ताकि उनकी कृषि संबंधी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके।

**श्री शत्रुघ्‍न सिंह, मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन**

मुख्‍य सचिव, उत्तराखंड शासन ने सुझाव देते हुए निर्देशित किया कि सर्व प्रथम यह ज्ञात किया जाए कि राज्‍य में कुल कितने स्‍वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। कितने समूहों का बैंक लिंकेज किया गया है साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कितने एस.एच.जी. सक्रिय हैं, कितने निष्क्रिय हैं, जिसकी समीक्षा हेतु नाबार्ड के साथ एस.एल.बी.सी. के स्‍तर पर एक कार्यकारी / अनुवीक्षण समिति का गठन किया जाए।

केंद्र सरकार की स्‍टार्ट-अप इण्डिया योजना के तहत दलितों एवं महिलाओं को ॠण उपलब्‍ध कराए जाने का प्रावधान है। उन्‍होंने कहा कि राज्‍य में इस योजना की प्रगति हेतु एक कार्ययोजना तैयार की जाए और समय-समय पर प्रगति की समीक्षा की जाए। एस.एच.जी. के माध्‍यम से राज्‍य में स्‍त्री शक्ति के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की प्रबल संभवाना है। इसलिए सभी बैंकों को चाहिए कि वे महिला उद्ममियों को विशेषकर एस.एच.जी. को उदारतापूर्वक बिना गारंटी के ॠण प्रदान करें, जिससे कि महिलाएं आर्थिक रुप से स्‍वावलम्बित हो सकेंगी।

मुख्य सचिव महोदय ने राज्‍य की प्रगति में एम.एस.एम.ई. सेक्‍टर की महत्वता को देखते हुए सभी बैंकों को निर्देशित किया कि इस सैक्टर पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और विभिन्न गतिविधियों हेतु सुगमतापूर्वक ॠण उपलब्‍ध कराए जायें।

उन्‍होंने आगे कहा कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्‍य तभी पूर्ण होगा जब बैंकों द्वारा दूरस्‍थ पहाड़ी क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा उपलब्‍ध करा दी जाएगी, परंतु अब भी कई दुर्गम स्‍थानों पर बी.एस.एन.एल. की ब्रॉड बैण्‍ड / वाई.-मैक्‍स कनेक्टिविटी उपलब्‍ध न होने के कारण बैंक को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में अनावश्‍यक कठिनाई हो रही है।

**श्री सी. पी. मोहन, मुख्‍य महाप्रबंधक, नाबार्ड**

मुख्‍य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने स्‍वयं सहायता समूहों लिंकेज हेतु सभी बैंकों से शीघ्रतापूर्वक कार्य करने का आग्रह किया तथा बैंक लिंकेज में कोई परेशानी आने पर नाबार्ड से सहायता ली जा सकती है। इस संबंध में शाखा स्‍तर पर सभी अग्रणी जिला प्रबंधक एवं राज्‍य सरकार के रेखीय विभाग से समन्‍वय स्‍थापित करने पर जोर दिया जिससे कि समूहों को समय पर सी.सी.एल. एवं टी.एल. प्राप्‍त हो सके। उन्होंने सदन के समक्ष “**क्षेत्र विशेष विकास कार्यक्रम**” के विषय में जानकारी दी एवं उससे संबंधित पावर प्‍वाइंट प्रस्‍तुतीकरण किया गया।

**श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव (एम.एस.एम.ई. एवं ग्राम्‍य विकास )**

प्रमुख सचिव महोदया ने बैंकों द्वारा एन.आर.एल.एम. योजना के अंतर्गत एस.एच.जी. समूहों का बहुत कम बैंक लिंकेज किए जाने पर खेद प्रकट किया और कहा कि एस.एच.जी. के अंतर्गत बैंक, समूहों के स्थान पर अब भी अधिकतर व्यक्तिगत ऋण प्रदान कर रहा है। उन्‍होंने कहा कि सभी बैंक जिला स्‍तर पर अग्रणी जिला प्रबंधकों / जिला ग्राम्‍य विकास विभाग के सहयोग से एस.एच.जी. बैंक लिंकेज कैम्‍प का आयोजन करें, ताकि लक्ष्‍य की शत प्रतिशत प्राप्ति हो सके।

उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में हेंडलूम सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए बैंकों को चाहिए कि वे बुनकरों को अधिक से अधिक वीवर क्रेडिट कार्ड जारी करें।

**श्री एम. बी. दिवाकर, उप महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक**

उप महाप्रबंधक, भारतीय स्‍टेट बैंक ने माननीय मुख्‍यमंत्री जी एवं सभी शीर्ष अधिकारियों को 55वीं एस.एल.बी.सी. बैठक में पधारने एवं मार्गदर्शन देने के लिये हार्दिक धन्‍यवाद किया। उन्‍होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि वे “**मुद्रा योजना**” के अंतर्गत छोटे उद्ममियों एवं व्‍यवसाइयों तथा स्‍वयं सहायता समूहों को अधिक से अधिक ॠण वितरित करें। उन्होंने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक पहल करते हुए माह जनवरी 2016 में देहरादून और हल्द्वानी पर “**एस.एच.जी. मेगा कैंप**” का आयोजन कर, अधिक से अधिक संख्या में बैंक लिंकेज करवाएगा।

उन्‍होंने बैठक में पधारे शासन के उच्‍च अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों एवं बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये धन्‍यवाद किया।